

बाल सामूहिक बलात्कार कानून की वैधता

प्रलिस के लयः

सर्वोच्च न्यायालय, धारा 376-DB, धारा 376-AB, भारतीय दंड संहति, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 ।

मेन्स के लयः

भारतीय दंड व्यवस्था में आजीवन कारावास में आवश्यक सुधार ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र में नौ वर्ष की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के जुरम में उमरकैद की सज़ा काट रहे एक 29 वर्षीय व्यक्तिद्वारा [सर्वोच्च न्यायालय](#) में याचिका दायर की गई है ।

- **सर्वोच्च न्यायालय** उस कानून की वैधता की जाँच करेगा जो 12 वर्ष से कम उमर के बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार के जुरम में दोषी व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास या अपराध का प्रायश्चिति अथवा सुधार करने का अवसर दिये बगैर फाँसी की सज़ा देता है ।

याचिका में रेखांकित मुद्दे:

- **न्यायाधीश के वकिलों को प्रतर्बिधति करना:**
 - इसने तर्क दया क [भारतीय दंड संहति](#) की धारा 376DB (12 वर्ष से कम उमर के बच्चे का सामूहिक बलात्कार) ने ट्रायल न्यायाधीशों को प्राप्त वकिलों को व्यक्ति के शेष जीवन के लिये सज़ा अथवा मृत्युदंड तक सीमति कर दया है ।
 - हालाँकि आजीवन कारावास प्रावधान के तहत न्यूनतम, अनविरय सज़ा का प्रावधान कया गया है ।
- **वर्ष 2018 के संशोधन में व्याप्त वसिंगति:**
 - याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दया क अगस्त 2018 में कये गए अपराधिक संशोधनों के माध्यम से नरिमति दंड प्रणाली में एक वसिंगति है ।
 - **धारा 376DB को वर्ष 2018** में पेश कया गया था जब बलात्कार के अपराध के लिये कठोर सज़ा प्रदान करने के लिये दंड संहति में संशोधन कया गया था ।
- **मनमानी:**
 - जबकि धारा 376-AB में 12 साल से कम उमर की लड़की से दुष्करम के दोषी व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान था ।
 - जबकि धारा 376-DB में 12 साल से कम उमर की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिये **आजीवन कारावास की अनविरय न्यूनतम** सजा का प्रावधान है ।
 - दोनों धाराओं में अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान है ।
 - बनि छूट के इस आजीवन कारावास का मतलब उस व्यक्ति के लिये 60-70 साल की जेल हो सकती है जिसकी आयु अभी 20 वर्ष से कम है ।
- **जीवन के अधिकार का उल्लंघन:**
 - धारा 376DB ने नचिली न्यायालय को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की उच्च सजा के अलावा कोई वकिल्प नहीं दया ।
 - याचिका में तर्क दया गया क धारा 376DB संवधान के [अनुच्छेद 21](#) (जीवन का अधिकार) और [अनुच्छेद 14](#) (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करती है ।
- **वैश्विक परदृश्य:**
 - इस मुद्दे के वैश्विक संदर्भ को देखते हुए, वटिर बनाम यूनाइटेड कगिडम के मामले में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया क पौरोल की वास्तविक संभावना के बनि आजीवन कारावास मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन था ।
 - यह माना गया क आजीवन कारावास को केवल सजा नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने कैदी को प्रायश्चिति का कोई अवसर प्रदान नहीं कया और ऐसे वाक्य मानवीय गरमि के सम्मान के साथ असंगत थे ।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय ने माना था क चरम मामलों में असंगत वाक्य ने आठवें संशोधन का उल्लंघन कया, जो

अमेरिकी संविधान क्रूर और असामान्य दंड को प्रतर्बिधति करता है ।

सर्वोच्च न्यायलय का दृष्टिकोण:

- सर्वोच्च न्यायलय ने अनविर्य मौत की सजा को असंवैधानिक बताते हुए पहले ही रद्द कर दिया है इसलिये ने इस सवाल पर वचिर करने की आवश्यकता बताई ।
 - इसके अलावा, इसने एक अतरिकित सॉलसिटर जनरल के साथ-साथ याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर लखिति प्रस्तुतियाँ और प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा ।
- ऐतहिसकि परपिरेकष्य:
 - वर्ष 1983 में 'मट्टू बनाम पंजाब' में सर्वोच्च न्यायलय ने फैसला सुनाया था कि आईपीसी की धारा 303 उस हद तक असंवैधानिक थी, जिसमें किसी अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काटते हुए हत्या करने वाले व्यक्तिको अनविर्य मौत की सजा का प्रावधान था ।
 - धारा 303 में यह अनविर्य कयिा गया है कि सर्वोच्च न्यायलय को ऐसे मामलों में मौत की सजा के अलावा कोई अन्य सजा नहीं देनी चाहिये ।

बाल संरक्षण के लिये संबधति अन्य पहल:

- [यौन अपराधों के खलिाफ बच्चों का संरक्षण अधनियिम \(पॉकसो\)](#)
- [बाल यौन उत्पीडन एवं शोषण रोकथाम](#)
- [बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना](#)
- [कशिोर नयाय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) संशोधन वधियक, 2021](#)
- [बाल वविह प्रतषिध अधनियिम, 2006](#)
- [बाल श्रम नषिध और वनियिमन अधनियिम, 2016](#)

स्रोत: द हनिदू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/validity-of-child-gang-rape-law>

